THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) The Government have, subject to legislative changes, decided to offer new coal blocks, without the restriction on coal mining for captive consumption only, to the Indian Companies including Public Sector Companies on the basis of competitive bidding. The successful bidder will be free to sell coal in the open market and will be allowed to charge any price negotiated between him and the consumer. The basic objectives of the above mentioned decision of the Government are to augment investment in coal mining, availability of coal and to improve its efficiency,It is expected that such a measure will increase competition and thereby lead to greater satisfaction to user industries.

(c) and (d) The assessment of the coal and lignite reserve to be allowed for private sector development will be done after the rules are framed.

(e) and (f) In a high level Committe meeting held on 15.11.1996 the matter of creation of land banks in States where large tracts of wasteland are available, was considered. It was concluded in the meeting that in view of the definite advantages of taking up compensatory afforestation in degraded forest land as compared to wasteland, the concept of a land bank in selected States to meet the requirements of the Central Projects may be dovetailed to a pool of such forest land. The concept of lasd bank once it comes into being would go A leng way in easing the problem of taking up compensatory afforestation and held expeditious issuance *of* forestry clearance for coal projects.

अमरीका और आस्ट्रेलिया में कोयला उत्पादन की कम लागत

890. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयले की उत्पादन लागत अमरीका और आस्ट्रेलिया की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन देशों में कोयले की उत्पादन लागत कम होने के कारणों का भी पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए है?

कोयला मंत्रालय को राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) तथा (ख) अमेरिका में कोयले का उत्पादन किए जाने संबंधी लागत के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1994 में कोल इंडिया लि. द्वारा अन्य देशों में कोयले की उत्पादन की लागत के संबंध में प्राप्त अद्यतन सूचना नीचे दी गई है:

	प्रति टन उत्पादन लागत	
देश	देश की मुद्रा में	भारतीय मुद्र में
जर्मनी (रुअर कोले) डच मार्क	250-300	5425-6510
युनाइटेड किंगडम पौण्ड (ब्रिटिश कोयला)	34-40	2077-2374
फ्रांस (लॉरेन कोलफील्ड)फ्रें. फ्रैंक	600-700	3860-4503
आस्ट्रेलिया डालर	20-35	563-984

(ग) तथा (घ) इस संबंध में प्रश्न ही नहीं उठता है, चूंकि वर्ष 1995-96 में भारत में कोयले की एक प्रति टन उत्पादन लागत 413 रुपए थी, जो कि उपर्युक्त विवरण में दी गई अन्य देशों की वर्ष 1994 को उत्पादन लागत से भी कम है।

Bill on Coal Policy

891. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have decided to introduce a Bill on Coal Policy in the current session of Parliament;

(b) if so, the main features of the policy;

(c) whether Govemment have taken any decision to open coal mining and exploration to the private sector; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (d) The Government have decided to move a Bill in the Parliament to amend the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 to allow any Indian Company to mine coal and lignite not only for captive consumption but also for sale. The Govemment have also decided to amend the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and to frame Rules for setting up of an independent body to step up exploration of coal and lignite resources and to allocate blocks on the basis of a competitive bidding process.

The basic objectives of the above mentioned decision of the Govemment are to augment investment in coal mining, increase availability of coal and to improve its efficiency. Thereby greater consumer satisfaction will ensue.

Diversion of supply of coal to black market

892. SHRI K.M. SAIFULLAH:
DR. MOHAN BABU:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether coal meant for tobacco farmers in Andhra Pradesh is being diverted to black market as reproted in News Time dated 16th January, 1997;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action proposed against the middlemen responsible for diversion?

THE MINISTER OF THE STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) The Tobacco Board and the Singareni Collieries Company Ltd. have reported that no complaint about diversion of coal has been received. The Govemment of Andhra Pradesh has also not reported detection of any case of diversion.

(b) and (c) Does not arise in view of answer to part (a).

बिहार में खनन/कोयला क्षेत्र में ठेके प्राप्त किया जाना

893. **श्री नरेन्द्र मोहन** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार में खनन/कोयला क्षेत्र में ठेके प्राप्त करने के लिए माफिया वर्ग के सक्रिय होने की जानकारी है;

(ख) यदि माफिया वर्ग सक्रिय है तो उसे नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं:

(ग) क्या कोयला क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ठेके देने संबंधी नियमों को सार्वजनिक रुप से घोषित किया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि को इंडिया लिमिटेड तथा सरकारी क्षेत्र की अन्य कोयला कंपनियों द्वारा ठेके प्रदान किए जाते हैं; और

(ड़) यदि हां, तो प्रमुख ठेकेदारों के नाम क्या है और क्या इन ठेकेदारों के आपस में कोई व्यापारिक या पारिवारिक संबंध हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती क्रांति सिम्ह) : (क) और (ख) इस संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर इस संकट (क्रियाकलापों) से निपटने हेतु कार्रवाई की जाती है।

(ग) विभिन्न प्रकार के ठेकों को दिए जाने के बारे में अखबारों के माध्यम से निविदाओं को आमंत्रित किए जाने संबंधी नोटिस में ठेके दिए जाने के बारे में शर्तों के संबंध में ब्यौरे समाहित किए जाते हैं।

(घ) जी, हां।

(ड) मुख्य ठेकेदारों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए) कोयला कंपनियां ठेकेदारों के साथ व्यापारिक अथवा पारिवारिक पार्श्विका का संबंध नहीं रखती है।

विवरण

बिहार में कार्यरत मुख्य ठेकेदारों के नाम

(किसी एकल ठेके में 50 लाख रु. तथा इससे अधिक की लागत के ठेके)

1. सीमा सड़क संगठन (भारत सरकार का उपक्रम), महा प्रबंधक का कार्यालय, नई दिल्ली तथा धनबाद स्थित मुख्य अभियंता का कार्यालय।